GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.*50
TO BE ANSWERED ON 21ST JULY, 2022

STEPS TO CREATE JOBS IN THE COUNTRY

***50. SHRI K.C. VENUGOPAL :**

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that around 25 per cent of youth job-seekers could not find work in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that a large number of posts either vanished or removed from various sectors during the last three years;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the steps being taken by Government to create jobs in the country?

ANSWER

MINISTER FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (e): A Statement is laid on the Table of the House.

*

Q.No. 48 & Q.No. 50 were taken up together.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *50 DUE FOR REPLY ON 21.07.2022 BY SHRI K.C.VENUGOPAL REGARDING "STEPS TO CREATE JOBS IN THE COUNTRY"

(a) & (b): The data on Employment and Unemployment is collected through Periodic Labour Force Survey (PLFS) conducted by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) since 2017-18. The survey period is July to June of next year. As per the available Annual PLFS reports, the estimated Unemployment Rate (UR) on usual status for youth of age 15-29 years was 17.3%, 15.0% and 12.9% during 2018-19, 2019-20 and 2020-21, respectively, which shows that the unemployment rate among the youth has a declining trend.

(c) to (e): As per the available Annual PLFS reports, the estimated Worker Population Ratio (WPR) on usual status for age 15 years and above has increased from 47.3% in year 2018-19 to 50.9% in 2019-20 and 52.6% in 2020-21. This indicates that people getting employment has risen during the period.

Employment generation coupled with improving employability is the priority of the Government. Accordingly, the Government of India has taken various steps for generating employment in the country. The Government of India has announced Aatmanirbhar Bharat package to provide stimulus to business and to mitigate the adverse impact of Covid 19. Under this package, the Government is providing fiscal stimulus of more than Rupees Twenty Seven lakh crore. This package comprises of various long term schemes/ programmes/ policies for making the country self-reliant and to create employment opportunities.

The Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) was launched with effect from 1st October, 2020 to incentivize employers for creation of new employment and restoration of loss of employment during Covid-19 pandemic. The terminal date for registration of beneficiaries was 31.03.2022. As on 13.07.2022 benefits have been provided to 59.54 lakh beneficiaries.

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) is being implemented by the Government for facilitating self-employment. Under PMMY, collateral free loans upto Rs. 10 lakh, are extended to micro/small business enterprises and to individuals to enable them to setup or expand their business activities. Upto 08.07.2022, 35.94 crore loans were sanctioned under the scheme.

Budget 2021-22 launched Production Linked Incentive (PLI) schemes, with an outlay of Rs. 1.97 lakh crore, for a period of 5 years starting from 2021-22. The PLI Schemes being implemented by the Government have potential for creating 60 lakh new jobs. All these initiatives are expected to collectively generate employment in the medium to long term through multiplier-effects.

PM GatiShakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by seven engines, namely, Roads, Railways, Airports, Ports, Mass Transport, Waterways and Logistics Infrastructure. This approach is powered by Clean Energy and Sabka Prayas leading to huge job and entrepreneurial opportunities for all.

Government is implementing Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi Scheme) since June 01, 2020 to facilitate collateral free working capital loan to street vendors to restart their businesses, which were adversely impacted during the Covid-19 pandemic. As on July 11, 2022, 33.34 lakh loans amounting to ₹3,615 Crore have been disbursed to 30.26 lakh beneficiaries under the scheme.

The Government of India is encouraging various projects involving substantial investment and public expenditure on schemes like Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Pt. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) and Deen Dayal Antodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) etc. for employment generation.

Further, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) is implementing the National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) and Pradhan Mantri Kaushal VikasYojana (PMKVY) to enhance the employability of youth.

Besides these initiatives, various flagship programmes of the Government such as Make in India, Start-up India, Stand-up India, Digital India, Smart City Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Housing for All etc are also oriented towards generating employment opportunities.

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *50

गुरूवार, 21 जुलाई, 2022/30 आषाढ़, 1944 (शक)

देश में रोजगार सृजन हेतु उठाए गए कदम

***50. श्री के.सी. वेणुगोपालः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में रोजगार के अवसर ढूँढ़ने वाले नौजवानों में से 25 प्रतिशत नौजवानों को काम नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विगत तीन वर्षों के दौरान विविध क्षेत्रों में अधिकांश पद या तो हटा दिए गए हैं या फिर उन्हें समाप्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

प्र.सं. 48 और प्र.सं. 50 पर साथ-साथ चर्चा की गई।

"देश में रोजगार सृजन हेतु उठाए गए कदम" के संबंध में श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 21-07-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *50 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) एवं (ख): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर वर्ष 15-29 आयु के युवाओं की बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 17.3%, 15.0% एवं 12.9% थी, जो युवाओं के मध्य बेरोजगारी दर की गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

(ग) से (ङ): उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2018-19 में 47.3% से वर्ष 2019-20 में 50.9% एवं वर्ष 2020-21 में बढ़कर यह 52.6% हो गई है जो यह दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल की गई हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 13.07.2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा उनमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए, उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से मध्यम से लंबी अवधि में रोजगार का सृजन करने को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्याधिक अवसर पैदा होंगें।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 11 जुलाई, 2022 तक, इस योजना के तहत 30.26 लाख लाभार्थियों को ₹3,615 करोड़ की राशि के 33.34 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, रोजगार सृजन हेतु पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सबके लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

*****

श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव : सर, मैं केन्द्र सरकार को देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। ... **(व्यवधान)** ... देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले तीन साल में कई कदम उठाये हैं। ... **(व्यवधान)** ... मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के लिए जितने कदम उठाये हैं, उनके बारे में सदन को सूचित करें। ... **(व्यवधान)** ...धन्यवाद।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, उत्तर दीजिए।

श्री भूपेन्द्र यादव : उपसभापति महोदय, भारत में रोज़गार के आकलन की दृष्टि से नियमित रूप से पीएलएफएस किया जाता है। ...**(व्यवधान)**...पीएलएफएस के माध्यम से यह देखा जाता है कि देश में उपलब्ध कार्यबल में से कितने कार्यबल को कार्य मिला है।...**(व्यवधान)**... मैं सदन के सामने पीएलएफएस के जून 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के आंकड़े रखना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**...ये आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में कार्यबलों को रोज़गार की उपलब्धता हुई है। ...**(व्यवधान)**...उसके साथ ही साथ भारत सरकार के लेबर ब्यूरो ...**(व्यवधान)**...के द्वारा एक्विस का सर्वे किया जाता है। ...**(व्यवधान)**... एक्विस के सर्वे के अंतर्गत संस्थागत क्षेत्र में जो रोज़गार है...**(व्यवधान)**... उस संस्थागत क्षेत्र के रोज़गारों को किस प्रकार से बढ़ावा देना है, ,...**(व्यवधान)**... इसका भी पूरा विषय रखा गया है और मैं उन आंकड़ों को भी सदन के समक्ष रखता हूं। ...**(व्यवधान)**...भारत में पेरोल रिपोर्टिंग पर जो रोज़गार परिदृश्य है, वह यह दिखाता है कि हमारे देश में जो पी.एफ. है, उसकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ...**(व्यवधान)**...अभी हाल ही में...**(व्यवधान)**...मई में...**(व्यवधान)**...जो पी.एफ. के आंकड़े आए हैं, वे भी इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार के पेरोल में वृद्धि हुई है। ...**(व्यवधान)**...जहाँ तक रोज़गार बढ़ाने के उपायों का विषय है, ...**(व्यवधान)**... भारत सरकार के द्वारा संस्थागत क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाने के साथ ही साथ 'आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना', 'प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना', 'राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना', 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम', 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अभियान', 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन', 'पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना', 'ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान', 'पी.एम. स्वनिधि योजना', ''पं. दीनदयाल अंत्योदय योजना'', 'प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम', 'प्रधान मंत्री मुद्रा योजना', 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना', 'राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' आदि भी हैं। ..**(व्यवधान)**..

श्री उपसभापति : यह क्वेश्चन ऑवर है और क्वेचन ऑवर पर ही चर्चा होगी। ..**(व्यवधान)**..

श्री भूपेन्द्र यादव : उत्पादन से जुड़ी हुई परियोजना को विशेष रूप से..**(व्यवधान)**..भारत सरकार की जो स्कीम्स चल रही हैं, ..**(व्यवधान)**..उनमें भी रोज़गार वृद्धि का कार्य हो रहा है। ..**(व्यवधान)**..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Thambiduraiji on Q.No. 48.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I am very happy to hear the Minister saying that the hon. Prime Minister has created employment opportunities. ...*(Interruptions)*... At the same time, I want to know from the hon. Minister about the MNREGA programme. In many places, the people are not able to get their wages at the proper time. ...*(Interruptions)*... Therefore, I would like to know whether the Government has come forward to see that the grievances in the rural areas are redressed and the employment opportunities are created where women are suffering. Would the Government come forward to find a solution to pay them in time? I would like to know on this. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय उपसभापति महोदय, सरकार द्वारा 'मनरेगा' कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया जा रहा है।..**(व्यवधान)**.. इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान भी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार दिवसों के रोज़गार सृजन का कार्य किया गया है। ..**(व्यवधान)**..अगर माननीय सदस्य की ऐसी कोई विशेष शिकायत है तो वे निश्चित रूप से इसे मेरे संज्ञान में लाएं। ..**(व्यवधान)**..संबंधित मंत्रालय को उसका संज्ञान दिलाया जाएगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are no supplementary questions on Q.No.50. Now, Q.No.49, Shri K.R.N. Rajeshkumar. The questioner is not present. Are there any supplementaries?

**49. [The questioner was absent.]*